

सम्पादकीय

इंडिया गठबंधनः कैसा बंधन

सफल लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और मजबूत विपक्ष को प्रजातन्त्र की मजबूती भी कहा जाता है। इसका एक ही कारण होता है कि लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए ही काम करती है। यह कार्य वह शासक भाव से नहीं बल्कि सेवाभाव से करती रहे इसके लिए जनता द्वारा चुना गया विपक्ष ही उसकी निगरानी भी करता है अतः सरकार को लगातार सेवाभाव में देखने का काम विपक्ष ही करता है क्योंकि वह भी सत्तारूढ़ पक्ष की तरह ही जनता द्वारा विभिन्न लोकतन्त्रिक सदनों में चुनकर भेजा जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली में चुने हुए सदनों के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सन्तुलन बनाये रखने के लिए इन्हें चलाने के ऐसे नियम बनाये गये जिससे कभी भी सरकार सेवाभाव की जगह शासक भाव में न जा पाये। इसकी तपसील में जाना इस सम्पादकीय में संभव नहीं है क्योंकि आज देश के सामने तो विपक्ष की ही समस्या है। 28 विपक्षी दलों को जोड़कर जो ईंडिया गठबन्धन इसी साल के जून महीने में बनाया गया था वह पहले ही झटके में तार-तार होता नजर आ रहा है और इसके सिपाही आपस में ही एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि इस गठबन्धन का गठन ही केन्द्र में मजबूत विपक्ष खड़ा करने के उद्देश्य से हुआ था। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में इस गठबन्धन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान हारने से इसमें शामिल अन्य दल इतने निराश हो गये हैं कि उन्हें सारा दोष कांग्रेस पर ही मढ़ने में ही अपनी विजय नजर आ रही है। इससे अन्दराजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान राजनीतिज्ञों की सोच कितनी निजपकर और संकीर्ण दृष्टि की है। मगर ईंडिया के अधिसंख्य क्षेत्रीय दलों को यह भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की चन्द्रशेखर राव सरकार को किस तरह हराया है। भारत राष्ट्र समिति एक क्षेत्रीय पार्टी है। अभी तक यह अवधारणा बनायी जाती थी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को उनके अपने घर में नहीं हरा सकती। तेलंगाना जीतकर कांग्रेस ने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया है। दरअसल ईंडिया गठबन्धन लोकसभा चुनावों के लिए बना था। विधानसभा चुनावों के लिए यह गठबन्धन नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के सहयोगी दलों को इन चुनावों में उसे समर्थन देना चाहिए था मगर बजाय समर्थन के कई दलों में कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध में अपने उम्मीदवार उतार दिये। आम आदमी पार्टी तो मिजोरम तक में जाकर चुनाव लड़ी जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 70 स्थानों पर चुनाव लड़ा। राजस्थान में भी आप पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। बेशक लोकतन्त्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है मगर आपस में तालमेल बैठाने या दोस्ती करने का फैसला तो राजनीतिक पार्टियां खुद ही करती हैं। अतः केवल एक दल को कैसे जिमेदार बनाया जा सकता है। जबकि किसी भी राजनीतिक गठबन्धन की हकीकत यह होती है कि इसमें विभिन्न विचारधाराओं व सिद्धान्तों की पार्टियां एक साझा मंच तैयार करती हैं जिससे वह अपने से मजबूत समझे जा रहे सत्तारूढ़ दल का मुकाबला कर सकें। अतः गठबन्धन में प्रत्येक पार्टी को अपने निजी हित छोड़कर समग्र हितों के बारे में सोचना होता है लेकिन यहां तो जगब हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी कह रही है कि क्या मुझसे पूछकर खड़े जी ने 6 दिसम्बर को ईंडिया की बैठक बुलाई थी। अखिलेश यादव इसी बात पर बिफरे बैठे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ ने उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीटें क्यों नहीं दी? आखिरकार यह बैठक ही रद्द कर दी गई। इससे यही साबित होता है कि ये क्षेत्रीय दल तेलंगाना में कांग्रेस की जीत से खुश नहीं हैं और उत्तर भारत के तीन राज्यों में हुई उसकी पराजय को पूरे ईंडिया गठबन्धन की गारं खोलने वाला मान रहे हैं। यह नजरिया न तो गठबन्धन का हो सकता है और न देश में मजबूत विपक्ष खड़ा करने का। यदि लोकतन्त्र को भारत में मजबूत बनाना है तो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को सबसे पहले अपने स्वार्थ छोड़ने होंगे और देश को सर्वोपरि मानना होगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की राजनीति में गठबन्धन का प्रयोग भारत में पहली बार हो रहा है। सबसे पहले 1967 में नौ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन इसी सिद्धान्त के तहत हुआ था। उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनावों में भी ईंदिरा गांधी के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दलों ने गठबन्धन किया था जिसे चौगुटा कहा गया था।

इसके बाद 1977 के चुनावों में भी सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने

इसके बाद 1977 के चुनाव में भा सभा प्रमुख विपक्ष दल न

इंडिया ब्लॉक को विधानसभा चुनाव नतीजों से उचित सबक लेना होगा

पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव परिणाम अप्रैलधर्मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से ठीक चार महीने पहले भाजपा विरोधी विपक्ष को अशुभ संकेत भेज रहे हैं। तीन उत्तर भारतीय राज्यों- मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हाथों कांग्रेस की हार एक आपदा है। भाजपा की इस भारी जीत का प्रभाव राष्ट्रीय फलक पर बीआरएस को हराकर तेलंगाना में कांग्रेस की जीत को बेअसर कर देगा। राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों से कई सबक मिलते हैं सबसे महत्वपूर्ण है देश के इन तीन प्रमुख राज्यों में मतदाताओं के राजनीतिक मूड में भाजपा के पक्ष में स्पष्ट बदलाव। यह सीमांत नहीं है, यह बहुत अधिक है

में भाजपा को हरा दिया था। 2019 के लोकसभा नतीजों को कई लोगों ने नरेंद्र मोदी फैक्टर का जिक्र करके समझाया। अब लोकसभा चुनाव की पूर्वसंध्या पर इन तीनों राज्यों में से किसी में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। मोदी फैक्टर को छोड़ दें, केवल राज्य चुनाव प्रचार के आधार पर, कांग्रेस के पास इन तीन राज्यों में मतदाताओं को देने के लिए कुछ भी नया नहीं होगा। 2024 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी लोकसभा सीटों को वर्तमान 52 से बढ़ावकर 120 से अधिक करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि प्रमुख विपक्षी दल के लिए भारत ब्लॉक में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए न्यूनतम है, यदि भाजपा को केन्द्र की

पार्टी कभी भी अपने दम पर सत्ता में वापस नहीं आती। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और यहां तक कि बिहार के साथ भी यही स्थिति रही है। तेलंगाना में, यह प्रवृत्ति उलट गई है और इससे कांग्रेस आलाकमान को दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और केरल में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य मिल सकते हैं।

उपर्युक्त पार्टी द्वारा विनाशक राय तैयार किए गये उपर्युक्त

में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। यह इस विश्वास का परिणाम था कि पार्टी विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब, अखिलेश कांग्रेस पर अपनी शर्तें थोप सकते हैं, तथा अन्य सहयोगी निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। अखिलेश इस बात से भी चिंतित है कि उन्हें परी द्वारा शाजमान नहीं निर्विवाद स्थापित करना चाहिए।

काग्रस पाटी के लिए दिक्कत यह है कि लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलने की चुनौती इश्क कम है। पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हिंदी भाषी राज्यों से होना है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा, अन्य हिंदी भाषी राज्य बिहार, झारखण्ड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। बिहार और झारखण्ड में काग्रेस पहले से ही गठबंधन सरकार का हिस्सा है। ताजा नतीजे इन गठबंधन राज्यों में अपने सहयोगियों से अधिक लोकसभा सीटों के लिए काग्रेस की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर देंगे। जहां तक इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का सवाल है, ततीजों ने खतरा भी पैदा किया है और कुछ अवसर भी। काग्रेस विधानसभा चुनावों में अच्छी जीत की उम्मीद कर रही थी और उस आधार पर, 2024 के चुनावों के लिए सीट बट्टवारे के संबंध में बेहतर सौदेबाजी की शक्ति के साथ आगामी विपक्षी गठबंधन बैठक में भाग लेने की योजना बना रही थी। वह लाभ अब नहीं रहेगा। अपमानित और निराश काग्रेस नेतृत्व सीट बट्टवारे के फाँसूले सहित विधानसभा चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 6 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेगा। बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में सहयोगियों के लिए भाजपा की चुनौती कड़ी होगी। खासकर बिहार में यह अपने चरम पर पहुंचेगा जहां भाजपा के सभी हमलों के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। भाजपा यह सोचकर कि जाति जनगणना की मांग को तीन राज्यों में मतदाताओं ने खारिज कर दिया है, आने वाले महीनों में नेंद्र मोदी की गारंटी के आधार पर जोरदार प्रचार करेगी। जद(यु) और राजद दोनों स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। काग्रेस को राज्य चुनाव से पहले अपने पहले के अनुमानों के विपरीत कम संख्या में सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का होगा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बट्टवारे पर अंतिम फैसला। हाल के हफ्तों हिंदू में भाजपा का जाति नियन्त्रित रूप से राज्य भाजपा को उत्साहित करेगी जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कारण पहले से ही लाप्रप्रद स्थिति में है। संक्षेप में, हिंदी भाषी राजनीतिक परिवर्श्य इंडिया गुट के लिए अनुकूल नहीं हैं। जो पार्टियां विधानसभा चुनाव नतीजों से थोड़ी भी अद्भुती रहीं, उनमें तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल और डीएमके शामिल हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में पुनरुत्थान वाली भाजपा का सामना करेगी, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उनका संगठन बिखरी हुई भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनावों के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वह हमेशा चाहती थीं कि सीट बट्टवारे पर बातचीत सिंतंबर में सुरक्षा हो लेकिन काग्रेस ने नतीजों की घोषणा तक इसमें देरी की। अब जब सीट बट्टवारे पर बातचीत शुरू होगी, तो टीएमसी सुप्रियोगे कमज़ोर काग्रेस से निपटेंगी, अगर काग्रेस अंततरूल टीएमसी के साथ गठबंधन करने का फैसला करती है। जहां तक दो वामपंथी दलों, सीपीआई और सीपीआई (एम) का संबंध है, सीपीआई को काग्रेस के साथ गठबंधन के परिणामस्वरूप तेलंगाना में एक सीट मिली। काग्रेस के साथ सीपीआई (एम) को गठबंधन वार्ता टूट गई। पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली। सीपीआई (एम) ने राजस्थान में अपनी दो सीटें खो दीं। यह पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि किसान आंदोलनों के जरिए पार्टी राजस्थान में अच्छा आधार बनाने में सफल रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीपीआई (एम) के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम केल से होगा। कुल 20 सीटों में से सीपीआई (एम) के पास अब केवल एक सीट है। काग्रेस के नेतृत्व वाले यूटीएफ को अन्य 19 सीटें मिली हैं। यह दोनों मोर्चों एलटीएफ और यूटीएफ की संबंधित ताकत के अनुपात से अधिक है। सीपीआई और सीपीआई (एम) दोनों के पास 2024 के लोकसभा चुनावों में यूटीएफ सहयोगियों से सीटें हासिल करने का अच्छा अवसर है।



चुनाव प्रचार के अंतम समय तक यह धारणा थी कि इस साल मई में हिमाचल और इससे भी अधिक कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस को चुनावी लड़ाई में बढ़त मिल रही है। 3 दिसंबर के नतीजों से पता चला है कि हवा भाजपा के पक्ष में बदल गई है और इससे हिंदू भाषी राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पलटवार की संभावना कम हो गई है। आइए इन तीन राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 65 सीटों में से भाजपा को 61 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 3 सीटें ही मिली थीं। यह परिणाम 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद आया था जिसमें कांग्रेस ने तीनों राज्यों

सत्ता से बदलखल करना है तो। 2003 के विधानसभा चुनावों में सभी राज्यों में हार के बावजूद, 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने इन तीन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया। वह बीस साल पहले की बात है और प्रधानमंत्री के रूप में कोई नेंद्र मोदी नहीं थे। कांग्रेस को गंभीरता से आत्मनिरक्षण करना होगा और देखना होगा कि अगले कुछ महीनों में धारणा को कैसे बदला जा सकता है।

www.tu...

2. [FAQs](#)

राजस्थान के माजपाया विधायिक एकारण में

जन पाच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नताज निकल ह, उनमें से एक राजस्थान भी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जीत हासिल की है। अभी वहां न तो सरकार बनी है और न ही मुख्यमंत्री चुने गये हैं, परन्तु उसके विधायक संक्रिय हो गये हैं। उनके एक विधायक कह रहे हैं कि वे माफियाओं को हूँड-हूँडकर नाश्ते में खायेंगे, तो एक अन्य विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नॉन वेज दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिये पुलिस अधिकारियों को फरमान जारी कर रहे हैं। विकास की बजाय उदयपुर के कन्हैयालाल की मौत के आधार पर भाजपा के पक्ष में जनादेश का सम्भवतरू यही साइड इफेक्ट हो सकता है। भाजपा की जीत का यह तत्काल प्रभाव भी कहा जा सकता है। अगर भाजपा के विधायक और नेता अपनी सरकार बनने से ताकत पाकर अभी से ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आने वाले समय में और भी कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। कहा जा सकता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, लेकिन ऐसे बयानों के चलते राज्य का सामाजिक माहौल कैसा बनेगा, उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। जयपुर के हवामहल से महज 600 वोटों से जीने वाले बालमुकुंद आचार्य ने विधायक पद की शपथ लिये बिना ही सोमवार को स्थानीय पुलिस को आदेश दे दिया कि शाम तक उनके क्षेत्र के नॉन वेज के सारे ठेले हटाये जायें। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके लाइसेंसों की जांच की जाये और उन्हें दिखालाया जाये। आचार्य ने पुलिस अधिकारियों से यह भी पूछा कि

व स्वयं रपाट दग था उन्हें पुलस स्टेशन आना पड़ा। राजस्थान मिल-जुली संस्कृति का प्रदेश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जाहिर है कि उनकी जीवन शैलियों में भी भिन्नता है। खान-पान सम्बन्धी रुचियां भी अलग-अलग हैं। चाहे शाकाहार हो या मांसाहार- सभी धर्मों के लोगों की जीवन पद्धति में दोनों ही तरह के भोजन शामिल हैं। धाम पीठाधिश्वर कहे जाने वाले बालमुकुंद आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे अपने मोबाइल पर किसी अधिकारी को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चांदी की टकसाल रोड पर मांसाहार की दुकानें हटा दी जायें। इस सङ्केत पर जितने भी ठेले खुले में नॉन वेज पदार्थ बिक रहे हैं, वे दिखने नहीं चाहिये। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी कि वे किसी को धमका नहीं रहे हैं बल्कि निवेदन कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने साफ किया कि उन्हें विधायक बनने का सर्टिफिकेट मिल गया है और अब वे किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे। उनका यह भी आरोप था कि कांग्रेस शासन में अधिकारी टालमटाल करते थे परन्तु वे इस बात को बर्दाशत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि उनके क्षेत्र के लोग खुले में मांस का व्यवसाय होते देखना पसंद नहीं करेंगे। उनकी शिकायत थी कि इसकी आड़ में गोमांस का भी कारोबार होता है। बालमुकुंद आचार्य अखिल भारतीय संत समाज की राजस्थान शाखा के प्रमुख हैं। वे हर ऐसे मामले में हिन्दुओं का पक्ष लेने पहुंचते हैं जहां किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक टकराव होता है। पिछले दिनों वे अपने एक और बयान के लिये चर्चा में आये थे जिसमें उन्होंने कहा

किया जा चुका है। उन्होंने ऐसे सैकड़ों मंदिरों के उनके पास प्रमाण होने का भी दावा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे हर रोज ऐसे ही एक मंदिर में जायेंगे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। इन मंदिरों के पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार का भी उन्होंने संकल्प ले रखा है। देखना यह होगा कि विधायक बनने के बाद अपने बढ़े हुए रसूख व शक्तियों के साथ वे अपने अभियान को कैसा और किस तरह का अंजाम देते हैं। अब तो सरकार भी उनकी है और यह भी सम्भव है कि वहां बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाये। फिर तो उनका संकल्प पूरा होकर ही रहेगा। उधर दूसरी तरफ जयपुर की ही झोटवाड़ा सीट पर जीते भाजपा नेता कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठोड़ ने चेतावनी जारी कर दी है कि वे अब माफियाओं को ढूँढ़-ढूँकर निकालेंगे और नाश्ते में खाएंगे। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे कहते हैं- मैं माफियाओं को नाश्ते में खाता हूँ। जितने माफिया हैं वे कान खोलकर सुन लें कि अगर वे मुझको रोक सकते हैं तो रोक लें। अगर नहीं रोक सकते तो मैं माफियाओं को ढूँढ़-ढूँकर निकालूंगा, नाश्ते में खाऊंगा। हिम्मत है तो मुझे रोककर दिखा दो। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की निर्वत्तमान अशोक गहलोत सरकार ने लोगों के पक्ष में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं। राज्य के लोगों के लिये 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर दिया जा रहा था। साथ ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का भी एलान हुआ था। उनके द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना भी लाई गई थी जिसके अंतर्गत किसी भी तरह की बीमारी का 50 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा था।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾ ਪਾਂਡ ਸਿਵਰਾਤੇ ਨਾਂਦੀ

पांच में से तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में रविवार को मिली छप्पर फाड़ जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब अगले ही दिन संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, तो वे उत्साह से इस कदर लबरेज थे कि उन्होंने संसद के द्वार पर विषय को शकारात्मकताएँ का संदेश दिया और नफरत का भाव त्यागने की भी सलाह दी। उन्होंने विषय को समझाया कि शेषा करने से देश का उनके प्रति नजरिया बदलेगा जिसका उन्हें (प्रतिष्ठको) इसलिये राजनैतिक लाभ भी मिलेगा क्योंकि जनता उनसे (विरोधी दलों से) मोहब्बत करने लगेगी ए प्रधानमंत्री की उहें यह भी सलाह थी कि वे विरोध के लिये विरोध छोड़ें। तीन राज्यों में मिली पराजय का गुस्सा छोड़कर विषय को चर्चा में भाग लेने के प्रति आगाह करते हुए पीएम ने उनसे सरकार की कमियों पर सलाह देने के लिये भी आयंत्रित किया। उन्होंने यह भी इशारा किया कि विषयी दलों का यह रखैया पिछले नौ वर्षों से चला आ रहा है। जाहिर है कि वे इन शब्दों में अपने ही कार्यकाल का उल्लेख कर रहे थे। एक मजबूत एवं सामर्थ्यवान विषय की जरूरत बतलाकर मोदी ने सबको चकित भी कर दिया। प्रधानमंत्री के ये परामर्श ऊपरी तौर पर तो बेहद नेक नजर आते हैं और कोई भी यह नहीं कह सकता कि इस सीख को विरोधी नेताओं को नहीं अपनाना चाहिये। सबाल तो यह है कि क्या स्वयं मोदी इस कथित नकारात्मकता के भाव से ऊपर उठ चुके हैं? क्या उनमें विरोधी दलों एवं उनके नेताओं के प्रति नफरत का भाव कूट-कूटकर नहीं भरा हुआ है? सकारात्मकता का काढ़ा पिलाने की कोशिश करने वाले मोदी अगर ईमानदारी से अपने इन विचारों और खुद के आचरण पर ही गौर फरमाएं तो पाएंगे कि उनकी कथनी और करसी में धरती-आकाश सा फासला है। फिर भी, क्या ही अच्छा होता कि इस सलाह पर अमल की शुरुआत अगर उन्हीं से होती। जिन नौ वर्षों के दौरान के विषय के रखैये से मोदी व्यक्तित्व नजर आये, उसे अगर उन्हीं के बरक्स देखें तो उनका यह

वक्तव्य एक बड़े विरोधाभास से कर्तव्य कम नजर नहीं आता। अमूनन मीडिया से भागने वाले मोदी अब संसद का जवाब देते। अपने दो कार्यकालों के दौरान यह शायद चौथा या पांचवा मौका रहा होगा जब वे मीडिया के

काल में वे नजर ही नहीं आते। अक्सर चर्चा खत्म होने के बाद वे आते भी हैं तो उनके भाषणों में विपक्ष के सवालों के सिलसिलेवार या ताकिंक जवाब नहीं होते और न ही देश की चिंताओं को वे एडेस करते नजर आते हैं। तमाम महत्वपूर्ण विधेयक वे चर्चा के बगैर पास करते हैं। कोई अगर सवाल करे तो वे या तो उस पर बात ही नहीं करते या फिर ऐसे मुखर सदस्यों की आवाज को अपने सांसदों के शोर-गुल में दबवा देते हैं। इस पर भी उनके लिये उठाये जाने वाले अड़चन भरे सवालों या बयानों को संसदीय कार्यवाही से विलोपित कर दिया जाता है या सदस्यों को ही निलम्बित करा दिया जाता है। इस पर भी मन भरे तो उनके यहां केंद्रीय जांच एजेंसियां दस्तक देने लगती हैं। सर्वदलीय बैठक जूनियर मंत्रियों के हवाले के बीच स्वयं बाहर सभाएं करते हैं। सरकार की त्रुटियों पर विपक्ष के विचार आर्पत्रित करने का औदार्य दिखलाने वाले ये वही मोदी हैं जो अपनी आलोचना को विरोधियों द्वारा गलियां देना भी बतलाते रहे हैं। ऐसा वे संसद के बाहर व भीतर दोनों जगहों पर करते हैं। उनके कारोबारी मित्र गौतम अदानी या फिर चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ की बात की जाये तो वे इसे देश पर हमला बतलाने लगते हैं और अगर नोटबन्दी या जीएसटी की असफलताओं पर विपक्ष बात करे तो उसे देशविरोधी करार दिया जाता है। पिछले 70 वर्षों का बिला नागा रोज हिसाब मांगने वाले मोदी से सम्बन्धित कई सवाल अगर हो तो वे उन्हें मिलने वाली गलियों की संख्या बतलाने लगते हैं। या वे इस बात का रोना रोते हैं कि उन्हें क्या-क्या कहकर और कितने किलो गलियां दी गईं। अगर प्रधानमंत्री खुली चर्चा के इन्होंनी ही हिमायती हैं तो उन्हें अपने सांसदों, पार्टी प्रवक्ताओं, आईटी सेल, ट्रोल आर्मी से कहकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिये चलाए जा रहे अधियानों को रुकवाना चाहिये। सब जानते हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मोदी व उनकी भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के खिलाफ एक बेहद अलोकतात्त्विक अधियान का हिस्सा है। मजबूत प्रतिपक्ष की वकालत कर उसे खुली चर्चा का न्यौता ऐसा कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता जो देश को उसकी सबसे पुरानी और आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली काग्रेस से ही मुक्त होने का न केवल सपना दिखाए बल्कि उसका नारा भी दे और ऐसा करने के तमाम अलोकतात्त्विक कदम उठाये। खुद मोदी काग्रेस एवं सम्पूर्ण विपक्ष को अनेक प्रकार से बदनाम करने के अभियानों का (सफल) नेतृत्व करते आये हैं। वैसे जब प्रधानमंत्री संसद भवन को शोकतंत्र का मर्दिरश बतलाते हुए विपक्ष को ज्ञान दे रहे थे तो उनकी भाव-भीमा में विनम्रता व सहजता नहीं थी। सम्भवतरूप वे काग्रेस पर खास तौर पर तंज कसने और उसका मखौल उड़ाने के लिये प्रकट हुए थे। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। संसद के दस्तावेजों में उनके ऐसे अनेक भाषण संरक्षित होने चाहिये जो विपक्ष एवं राष्ट्र निमार्ताओं के लिये अपमानसूचक शब्दों से भरे पड़े हैं। उनका यही रवैया सदन के बाहर दिये जाने वाले भाषणों में भी रहता है। बहुत पीछे जाकर उनके पुराने वक्तव्यों को उद्धृत करने की बजाये हाल के उनके कुछ बयानों को देखें तो उनका व्यवहार उनकी इस ताजा सीख से एकदम अलग है। पुरानी संसद से नये भवन में जाने के पहले उन्होंने इसी जगह पर कहा था कि शिवपक्ष रोना-धोना छोड़कर नयी शुरूआत करें ऐसे-धोने से उनका आशय वही था जो इस बार की नकारात्मकता से है। यानी उन्हें असहज करने वाले प्रश्न न पूछे जायें और सरकार की हाँ में हाँ मिलाई जाये। मोदी की सकारात्मकता का यही आशय है। फिर, सवाल पूछने वाले उनके लिये शम्खों के सरदारश भी हो जाते हैं। अधिक पीछे गये बगैर मोदी के पिछले नौ वर्षों के राजनैतिक सफर को देखें तो कह सकते हैं कि सकारात्मकता अपनाने का जो संदेश वे दे रहे हैं उसकी शुरूआत उन्हीं से किये जाने की सख्त जरूरत है। आजाद मुल्क के गौरवशाली संसदीय इतिहास व लोकतात्त्विक विरासत को हमेशा गरियाने और विपक्ष विहीन भारत का नारा बुलन्द करने वाले मोदी ने जो बातें सोमवार को संसद भवन की दहलीज पर कीं, उसके एक छोटे से हिस्से पर भी वे अमल करें तो देश का न केवल लोकतंत्र बचा रहेगा वरन् देश भी बच जायेगा।

जो वार्डन अवैतनिक रहकर नागरिक सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्य के लिए डटे रहते हैं : जिलाधिकारी



बरेली। नागरिक सुरक्षा कोर के 61वें स्थापना दिवस के छठवें व अंतिम दिन कलेट्रेट परिसर स्थित नागरिक सुरक्षा कोर बरेली के तत्वावधान में जिलाधिकारी / नियंत्रक रविन्द्र कुमार ने नागरिक सुरक्षा के ध्वज उत्तरालन कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा के ध्वज को फहराया। इसके बाद संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा साहब डाउमीराव अंबेडकर जी की पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ए.डी.एम.सिटी

मिर्ची से लदे टेंपो को बदायूं हाइवे पर वाहन ने मारी टक्कर, चालक की मौत

बरेली। टेंपो से मिर्ची बेचने डेलापीर मंडी जा रहे युवक को बदायूं हाइवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे



में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। भौमारा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद गांव का रहने वाला खुशालीराम (50) मंगलवार देर रात मिर्ची बेचने टेंपो से डेलापीर सभी मंडी जा रहे थे। चाढ़पुर के पास टेंपो में अज्ञात वाहन की टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई और टेंपो पलट गया। मौका देखकर आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टेंपो को कब्जे में लेकर थाने भेजा। वहीं चालक की तलाश शुरू कर दी। मृतक के भाई वीरपाल ने बताया कि खुशीराम की जेब में रखे कागज से नंबर मिला। पुलिस ने परिवार में हादसे की सूचना दी। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी प्रेमवती का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रेमवती ने बताया कि उनके पति खेती करके बच्चों का पालन पोषण करते थे। उनके दो बेटे हैं।

बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओं पढ़वाड़े के तहत बालिकाओं को कारबा

गया ऐतिहासिक व अन्य स्थलों का एक्सपोजर विजिट

बरेली। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्था द्वारा बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओं पर खवाडा के अंतर्गत जनपद बरेली में महिला कल्याण विभाग की ओर से श्रीमती मोनिका राणा जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुभानगर की छात्राओं के साथ



एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। छात्राओं को वस द्वारा पहले महिला थाने सुरक्षा व्यवस्था बताई गई उसके बाद 300 बेटे हाँस्टिटल खुर्रम गोटिया में महिला सुरक्षा हूं पुलिस कार्रवाई कार्जसिलिंग मेंडिकल सुविधा बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करते हुए बरेली के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कराए गए तुलसी स्थल मंदिर के दर्शन कराए गए और प्राचीन इतिहास मंदिर का बच्चों के समक्ष समझाया गया। उक कार्यक्रम में श्रीमती मोनिका राणा जिला प्रोवेशन अधिकारी सौरभ सिंह सरक्षण अधिकारी सोनम शर्मा महिला कल्याण अधिकारी, श्रीमती चचल गंगवार केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेन्टर बरेली, दिनेश कुमार, देवेंद्र कुमार महिला कल्याण विभाग बरेली, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, नरेन्द्र पाल राष्ट्रीय महामंत्री, राकेश मौर्य उपाध्यक्ष रामकिशोर, श्रीमती नीलम शर्मा, श्रीमती मधुरिमा चद्रा अध्यापिका कर्स्टरवा गांधी आवासीय वालिका विद्यालय सुभानगर व अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु द्वारा बालिकाओं को महिला थाना बरेली, वन स्टॉप सेन्टर बरेली, जगन्नाथ टेम्पल बरेली, तुलसी मठ स्थलों का विजिट कराया गया।

मन से समाज सेवा में डटे रहना है। सभी वार्डन बिना किसी फल की चिन्ता किए अपने उत्तराधिकारियों का निर्वहन करते हैं, उसकी उन्होंने हृदय से प्रशंसन करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राकेश मिश्र ने नियंत्रक के सम्पर्क वर्ष वार्डन सर्व रंजीत द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष 90 से अधिक प्रशिक्षण कार्यविभिन्न जागरूकता के बार्डन वार्डन (आ) शिवलेश चन्द्र पाण्डे, सुनील यादव, संजय पाठक, डा.उस्मान नियाज़, बृजेश पाण्डे, अनवर हुसैन, हीरेश भल्ला, कंवलजीत सिंह, आर. वी.तिवारी, अनिल कुमार शर्मा, मोफहाज़, गिरेश साहनी, अशु कूरू, विवेक मिश्र, जहीर अहमद, सचिन जोशी, गीता दोहरे छबरा, रानी सिंह सहित 150 से ऊपर वार्डन सर्व रंजीत द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का विवरण

, विशिष्ट अतिथि ए.डी.एम.सिटी, सौरभ दुबे का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सृष्टि विन्ह में राष्ट्रीय विन्ह के प्रतीक अशोक की लाट भेंट की। सभी वार्डन साधियों का आभार व्यक्त किया। आज के इस कार्यक्रम में दोनों सहायक उप नियंत्रक पक्षज कुर्बानीया व प्रमोद जगर चहित डिविजनल वार्डन सर्व रंजीत विशिष्ट, डिविजनल वार्डन दिनेश यादव डिविजनल वार्डन हाइसेम मिश्र, डिविजनल वार्डन (आ) शिवलेश चन्द्र पाण्डे, सुनील यादव, संजय पाठक, डा.उस्मान नियाज़, बृजेश पाण्डे, अनवर हुसैन, हीरेश भल्ला, कंवलजीत सिंह, आर. वी.तिवारी, अनिल कुमार शर्मा, मोफहाज़, गिरेश साहनी, अशु कूरू, विवेक मिश्र, जहीर अहमद, सचिन जोशी, गीता दोहरे छबरा, रानी सिंह सहित 150 से ऊपर वार्डन सर्व रंजीत द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

वरेली। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एवं परिवहन नियम के विकास के लिए पुराना बस स्टेशन बरेली पर एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीड़ी मिश्रा प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा

महामंत्री ने बताया कि वह लगातार यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। कई बार प्रदर्शन भी किया गया। आज किर वह इस सभा के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि मंडलीय परिवहन विकास के लिए निजीकरण का विरोध और अनुबंधित बस मालिकों द्वारा अपने-परिचालक रखने की अनुमति का विरोध-संविदा कर्मचारियों का नियमित तत्काल की जाये। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का परिवहन नियम से संबद्ध किया जाये तथा परिश्रमिक बकाया दिया जाये। यूनियन के स्क्रीन मंत्री रविन्द्र पाण्डे ने कहा कि वह इस बैठक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर जल्द ही कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे जाकर वह चक्राजाम आंदोलन भी करें। बैठक के माध्यम से उन लोगों ने क्षेत्रीय प्रबंधक चौकरी को एक ज्ञापन के माध्यम से समस्या से अवगत कराया।

बरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने बाबा साहब के विरोध पर अन्यत्रित किए जाएं। अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) राजीव अग्रवाल सहित सभी शाखा अधिकारियों, यूनियन के

वरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने बाबा साहब के विरोध पर अन्यत्रित किए जाएं। अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) राजीव अग्रवाल सहित सभी शाखा अधिकारियों, यूनियन के

वरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने बाबा साहब के विरोध पर अन्यत्रित किए जाएं। अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) राजीव अग्रवाल सहित सभी शाखा अधिकारियों, यूनियन के

वरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने बाबा साहब के विरोध पर अन्यत्रित किए जाएं। अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) राजीव अग्रवाल सहित सभी शाखा अधिकारियों, यूनियन के

वरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सुश्री रेखा यादव ने बाबा साहब के विरोध पर अन्यत्रित किए जाएं। अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विवेक गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) राजीव अग्रवाल सहित सभी शाखा अधिकारियों, यूनियन के

वरेली। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिवारण दिवस के उपल

